मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

डॉक्टरों में बसते हैं कलाकार भी 3
दिमाग साफ करिये, पैर नहीं 4
चुनाव की सूली पर देश की प्रतिष्ठा! 5
शिशु मंदिर के छात्र की जुबानी 6
साक्षर भारत कार्यक्रम को बर्बाद किया 8

वर्ष 34 अंक -16 फ़रीदाबाद 3-9 मार्च 2019 फोन - 9999595632 2.50 ₹

बिल्डर लॉबी के लिए खट्टर सरकार ने अरावली का रास्ता कर दिया था साफ

संघी मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का बुलडोजर चलाया

फ़रीदाबाद (म.मो.) संघी गोद में बैठे सीएम खट्टर ने अरावली को बिल्डरों के हवाले करने के लिये पीएलपीए कानून में विधानसभा से संशोधन करा लिया। इस संशोधन पर स्टे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने खट्टर व उनके आकाओं के इरादों पर पानी फेर दिया। यहां तक कि अदालत अवमानना के आरोप में कार्यवाही की धमकी भी दे डाली।

सन् 1900 में अंग्रेज हुकूमत ने दिल्ली से सटे अरावली वन क्षेत्र को बचाये रखने के लिए पंजाब लैंड प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। इसके चलते अरावली वन क्षेत्र में पेड़ काटना व भवन निर्माण करना वर्जित एवं संज्ञेय अपराध माना गया था। इसी एक्ट के चलते फरीदाबाद अरावली के पूर्व तथा दक्षिण की ओर फैलता चला गया और गुड़गांवा इसके पश्चिम व दक्षिण की ओर बढ़ता गया। यद्यपि कुछ बिल्डरों ने राजनेताओं व न्यायपालिका से सांठ-गांठ करके कुछ कालोनियां विकसित कर मारीं तथा कुछ राजनेताओं व अफसरशाहों और

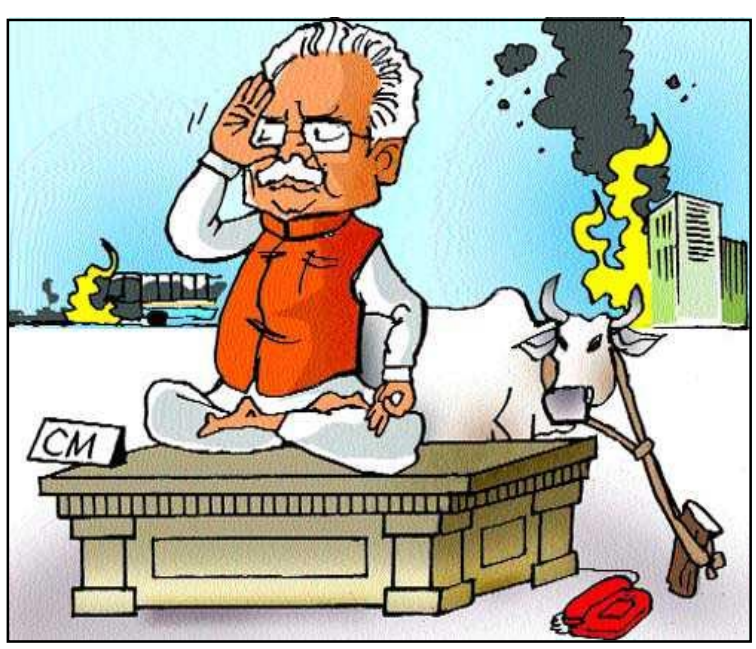

उसके लग्गुए-भग्गुओं ने भी अपने-अपने फार्म हाउस तथा बिजनैस हाउस खड़े कर लिये।

हरियाणा सरकार ने भी इस क्षेत्र में 'हूडा' के 4 सैक्टर विकसित करने का अभियान चलाया था। लोगों से आवेदन राशि भी ले ली थी परन्तु सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते राज्य सरकार का यह धंधा तो मंदा हुआ ही बिल्डरों को भी नकेल कसी जाने लगी। नकेल को ढीला करने के बदले नेताओं व अफसरों ने भी खूब लूट मचाई। इसके लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का एक चोर दरवाजा रखा गया। यानी जिसको सरकार अथवा उसके अफसर एनओसी जारी कर दें वह पेड़ भी काटेगा, निर्माण भी करेगा और इसके लिए आवश्यक खनन भी करेगा।

लेकिन भाजपाई खट्टर सरकार ने यह परचून की दुकान चलाने की बजाये एक झटके में ही सारे अरावली संरक्षित वन क्षेत्र को बेच खाने के लिए अंग्रेजों द्वारा निर्मित उक्त एक्ट को ही ऐसा संशोधित कर दिया कि बिल्डरों को यहां निर्माण करने में कतई कोई परेशानी न रहे।

देखा जाये तो हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की चाल पर अपना तुरुप का पत्ता फैंका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 1990 के बाद बने मकानों का धराशायी करने का आदेश जारी किया था। खट्टर सरकार ने अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस कानून को ही बदल दिया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अरावली का संरक्षित क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए फेफड़ों सरीखा है। आसपास के प्रदूषित क्षेत्र को शुद्ध वायु प्रदान करने वाला यह क्षेत्र जब नष्ट हो जायेगा तो पहले से ही प्रदूषित इस क्षेत्र की क्या दुर्दशा होगी, समझना कठिन नहीं। अब देखना यह है कि पर्यावरण एवं अरावली प्रेमी तथा न्यायपालिका सभी मिलकर इस मामले में क्या कर पाते हैं।

मंझावली यमुना पुल के बाद एक और तोहफे (सड़क) का झांसा दिया मंत्री गडकरी ने

2014 शिलान्यास की पुनरावृत्ति में मंत्री गूजर और गोयल आज भी तालियां ही बजा रहे हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के मीठापुर गांव में शुक्रवार को एक सड़क का शिलान्यास करके क्षेत्र की जनता को वैसा ही एक और झांसा दे दिया जैसा कि 15 अगस्त 2014 को मंझावली गांव में यमुना पुल का शिलान्यास करके दिया था। मंझावली पुल के दो साल में बनाने का वादा था जो आज लगभग पांच वर्ष बाद वहां सिर्फ तीन-चार खंभे खड़े हैं।

6 मार्गी 6 किलोमीटर यह सड़क दिल्ली, आश्रम चौक के निकट स्थित डीएनडी फ्लाईओवर से शुरु होकर कालिंदी कुंज होते हुए आगरा नहर व गुड़गांव नहर के साथ चलते हुए सैक्टर-37 से बाईपास में मिल जायेगी। बाईपास के अंतिम छोर कैली गांव से यह सड़क सोहना में केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेस-वे से मिल जायेगी।

जनता को सब्ज बाग दिखाने व झूठ बोलने की अपनी आदत के मुताबिक गडकरी, कृष्णपाल गूजर तथा विपुल गोयल आदि अन्य नेताओं ने इस सड़क के बन जाने पर जनता को होने वाले फायदों का बखान पूरे जोर-शोर से ठीक वैसे ही किया जेसे मंझावली के यमुना पुल से होने वाले फायदों का किया था। जबकि इस तरह के बखान की कतई कोई आवश्यकता नहीं होती। यह बात सारी जनता स्वत: जानती है कि कोई पुल अथवा सड़क बनने से क्या-क्या लाभ होते हैं

सुधी पाठक जान लें कि दिल्ली आश्रम से फरीदाबाद तक के ट्रैफिक भार को कम करने की यह योजना बीते बीसियों वर्ष से ठंडे बस्ते में पड़ी है। करीब 15 पूर्व इस

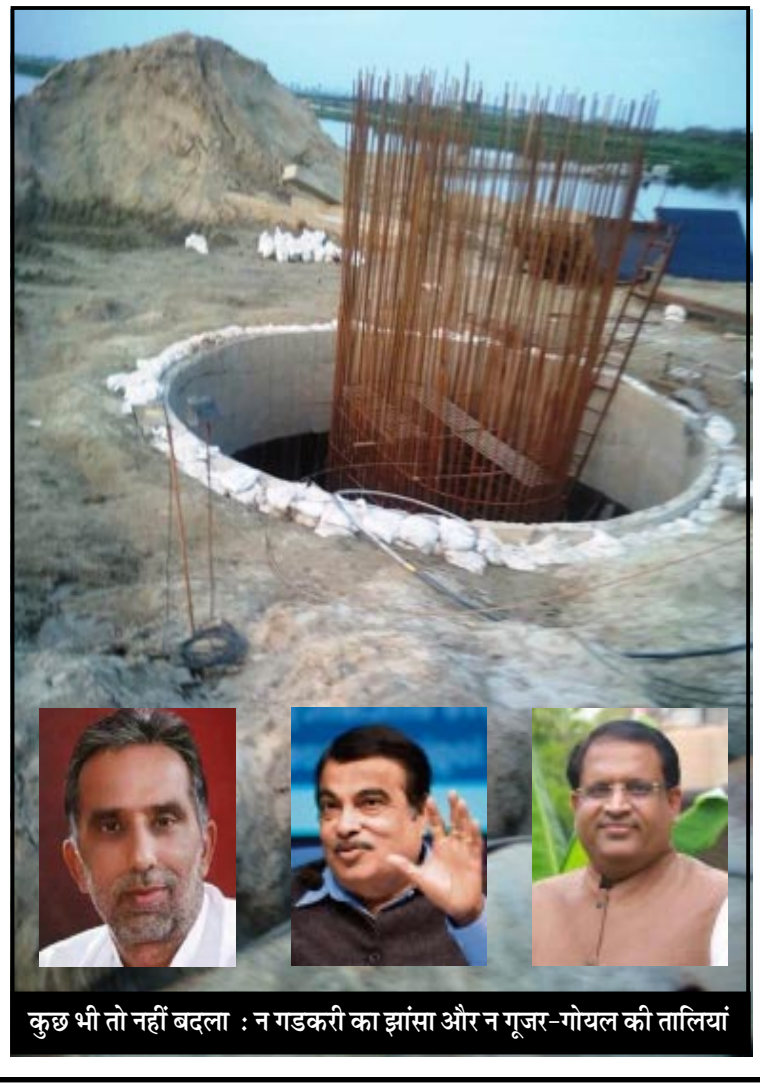

कुछ भी तो नहीं बदला : न गडकरी का झांसा और न गूजर-गोयल की तालियां

कृष्णपाल सहित भाजपाइयों की झूठ एवं जुमलेबाजी का कहां तक बखान करें ? 15 अगस्त 2014 को मंझावली गांव में यमुना पर जिस पुल की आधारशिला केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने रखते हुए इसे 2 साल में चालू करने का वायदा किया था, उसकी मौजूदा हालत इस चित्र में देखी जा सकती है। पुल के लिए बनने वाले कुल 48 पिलरों में से अभी तक केवल 3 पर ही काम चल रहा है। इतना ही नहीं इस 6 मार्गी पुल तक पहुंचने के लिए 5 गांवों के बीच से गुजरती संकरी सड़कों से ट्रैफिक को गुजारने की भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है। यदि कही, 2-4 वर्ष में यह पुल बन भी गया तो 15 किलोमीटर के उस संकरे मार्ग पर ट्रैफिक का वही होगा जो आज केजीपी मार्ग तक जाने वाली चंदावली से मौजपुर के बीच हो रहा है। आने-जाने वाले बताते हैं कि कुंडली से मौजपुर तक पहुंचने में डेढ़ घंटा और मौजपुर से चंदावली तक के ढाई घंटे लगते हैं। क्या लाभ ऐसे पुल और केजीपी बनाने का ?

प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हुए डीएनडी फ्लाईओवर के पास से मिट्टी भराई का काम भी शुरू हुआ था। लेकिन काम करने की जब नीयत न हो तो बहानों की कोई कमी नहीं रहती। इसके लिये बहाना बताया गया था कि कालिंदी कुंज के पास जो जमीन है वह यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की है। वैसे आगरा नहर के साथ-साथ भी इसी विभाग की जमीन है। इस तरह बहाना बनाकर काम ठप कर दिया गया।

सवाल यह पैदा होता है कि बीते 5 सालों से इसे बनाने का विचार क्यों नहीं आया? अब चुनाव की आचार संहिता लगने के समय ही उन्हें इसकी याद कैसे आ गयी? एक ओर पीएम मोदी के झूठे वायदों पर कटाक्ष करते हुए गडकरी कहते हैं कि वे वही वायदा करते हैं जो वे पूरा कर सकते हैं। उनके इसी झूठ का जीता जागता उदाहरण मंझावली का यमुना पुल है जिसे उन्होंने 15 अगस्त 2016 तक चालू कर देने का वायदा किया था।

ताजातरीन शिलान्यास वाले मार्ग पर बनने वाले पुलों व अंडरपासों की संख्या बताते हुए वे इस पर लगने वाली 3860 करोड़ की लागत का वर्णन तो करते हैं परन्तु इस बात को गोल कर जाते हैं कि यह रकम टोल टैक्स के माध्यम से जनता से ही वसूली जायेगी जिस पर उनका मोटा कमीशन तो होगा ही। यानी कि आने वाले समय में शहर का बाइपास भी टोल-टैक्स का शिकार होने वाला है। यह टोल टैक्स वही है जिसे सांसद व मंत्री बनने से पूर्व कृष्णपाल जजिया कर बताते थे।

यद्यपि इस सड़क के पूरा होने की कोई अवधि गडकरी ने बताई नहीं, परन्तु वे बता भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे मंझावली पुल की बताई थी। भाजपा की इन चुनावी कलाबाजियों को जनता बखूबी समझती है। यह पब्लिक है सब जानती है।